Supply of nuclear weapons material zironium to Pakistan

1733. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Statesman on the 23rd April, 1989 to the effect that two West German companies have admitted supplying nuclear weapons related material zironium to Pakistan and one of their sources was India and that it was relabelled as 'prime-quality steel' before being reshipped to Pakistan to help the clandestine nuclear efforts there; if so, what are the details thereof; and

(b) what precaution have been taken to curb the exports/smuggling of zirconium, uranium and similar other items and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) The policy of the Government is not to export, as a general rule, Zirconium, Uranium and other nuclear materials. Exceptions are made in special cases and in respect of small quantities of such materials to be supplied to countries for experiments under bilateral cooperation agreements in the field of peaceful uses of atomic energy. However, Nuclear Fuel Complex (NFC), Hyderabad had exported about 2.2 metric tonnes of Zircalloy tubes, rods and strips during 1983—85, in response to a request by M/s NTG Nuklear-technic Gmbh (NTG) of Federal Republic of Germany. In its telex order for purchase of Zircalloy materials for use in certain irradiation tests, NTG had indicated that the supplied Zircalloy would not be resold. The Government is awaiting clarifications from NTG regarding reports of diversion of India Zircalloy to Pakistan.

छावनी निधि सेवा नियमावली, 1937

1734. **श्री शरद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी निधि सेवा नियमावली, 1937 (संशोधित) के स्थानांतरण आदेश 5 (ख) दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 को हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 25 फरवरी, 1989 के निर्णय द्वारा निरस्त किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो स्थानांतरण आदेशों के निरस्त हो जाने के बावजूद लेखा अधिकारी, छावनी बोर्ड, बरेली को उसके पद पर रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन किए जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि छावनी बोर्ड कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के नियम लागू हों ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं । छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित छावनी निधि सेवक नियमावली, 1937 के नियम 5(ग) को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया ।

(ख) और (ग), (क) के उत्तर में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के आदेश से पहले ही उन्हें उनके ही अनुरोध पर वाराणसी से बरेली स्थानांतरित कर दिया गया था ।

(घ) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है ।